अल्पसंख्यक कल्याणार्थ 15 सूत्रीय कार्यक्रम

जयपुर,(कासं): राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की क्रियान्विति की समीक्षा के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के गैर सरकारी सदस्यों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मनोनयन किया है। राज्य स्तरीय समिति के लिए गैर सरकारी सदस्यों के रूप में अजमेर निवासी रणवीर सिंह खुराना, जैसलमेर निवासी जीवण खां और भीलवाड़ा निवासी मोहम्मद इरफान शेख का मनोनयन किया गया है। इसके साथ ही तीन प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के रूप में मोहम्मद खालिद गौरी, सरदार सुरेन्द्र सिंह और मुनासिफ अली का मनोनयन किया गया है। समिति की बैठक हर तीसरे महीने आयोजित की जाएगी। एक बैठक से दूसरी बैठक का अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होगा और त्रैमासिक बैठक की प्रगति रिपोर्ट अगले महीने के 15 दिवस तक केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी। समिति का मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देना होगा। समिति का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा।

अवकाश पर गए महत्वपूर्ण विभागों के अफसर

अतिरिक्त कार्यभार के सहारे चल रहे हैं सरकारी महकमे

दूसरे अफसर संभाल रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां

जयपुर (कासं)। महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के अवकाश पर जाने और कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के चलते सरकार को अतिरिक्त कार्यभार के सहारे कई विभागों को चलाना पड़ रहा है।

गर्मी में पेयजल संकट की स्थितियों से चर्चा में रहने वाले पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव ओपी सैनी के अवकाश पर जाने के कारण उनके पद का अतिरिक्त कार्यभार शासन सचिव दिनेश कुमार संभाल रहे हैं। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव अशोक सिंघ्वी के अवकाश पर जाने के कारण उनके पद का कार्यभार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी संभाल रहे हैं। इसी तरह श्रम विभाग के शासन सचिव रजत मिश्रा के अवकाश पर जाने के कारण उनके पद की जिम्मेदारी आयुक्त, पंचायतीराज राजेश यादव को सौंपी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश श्रीवास्तव को चेयरमैन, महिला आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। डायरेक्टर, पब्लिक सर्विस एंड कंट्रोलर, बन्नालाल को डायरेक्टर, मॉनीटरिंग प्रोग्राम एंड इम्प्लीटेशन को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी हुई है।

वैसे तो अधिकारियों के अवकाश पर जाने की स्थिति में किसी अन्य को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन एक साथ महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने से इस शासन सचिवालय में कामकाज पर असर देखा जा रहा है। आरएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही आरएएस अधिकारियों की एक और तबादला सूची जारी करेगी। जिसमें पदस्थापन की प्रतीक्षा में चल रहे आरएएस अधिकारियों को पदस्थापन दिया जाएगा।

आरएएस अफसरों के भी रिक्त हैं कई पद

आरएएस [illegible] प्रदेश के [illegible] कई जगह अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं, जिसके चलते अतिरिक्त कार्यभार के सहारे कई जिलों में उपखण्ड अधिकारियों के काम को संपादित किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश में प्रशासन लोक अदालत अभियान शुरू होने से पूर्व सरकार को इस समस्या से जूझना पड़ा था।

कई जिलों में उपखण्ड अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण लोगों के काम अटक गए। कार्मिक विभाग को प्रशासन लोक अदालत अभियान शुरू होने के बाद आदेश जारी करने पड़े, जिसमें कहा गया कि प्रशासन लोक अदालत अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाता है कि जिन जगहों पर उपखण्ड अधिकारी और एसीएम के पद रिक्त चल रहे हैं। उन पदों का अतिरिक्त कार्यभार जिले में पदस्थापित अन्य उपखण्ड अधिकारी और एसीएम को सौंप दिया जाए। हालांकि बुधवार को सरकार ने 40 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर कुछ जिलों में रिक्त चल रहे उपखण्ड अधिकारियों के पद पर नियुक्तियां दी हैं, लेकिन अब भी प्रदेश में कई जगह उपखण्ड अधिकारी और एसीएम के पद रिक्त हैं।

जनसुनवाई में शिकायत लेकर आने वालों में कमी आई

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को जनसुनवाई में सबसे कम कार्यकर्ता अपनी शिकायतें लेकर आए। गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में चार मंत्रियों ने सुनवाई की। इस दौरान करीब 40 कार्यकर्ताओं के आवेदन आए। गुरुवार को सरकार के चार मंत्री होते हुए भी अब तक की सबसे कम शिकायतें आई।

गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी,

■ ट्राई साइकिल के वितरण में गड़बड़ी के लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार : चतुर्वेदी

पंचायत राज मंत्री सुरेन्द्र गोयल, सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक और गोपालन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी। गुरुवार को चालीस शिकायतें आई इनमें भी ज्यादातर मामले तबादलों से जुड़े हुए थे। जनसुनवाई के दौरान अधिकांश शिकायत लेकर आने वाले कार्यकर्ता भी जयपुर तथा आसपास के इलाके के ही थे। जनसुनवाई के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंचायतराज मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों का समाधान हो रहा है, इसलिए अब भीड़ कम हो रही है।

उन्होंने शिक्षक तबादलों पर कहा कि यहां मिलने वाली अर्जियों को शिक्षा मंत्री के पास भेजा जा रहा है इन पर जो भी उचित कार्यवाई होगी शिक्षामंत्री करेंगे। मंत्री अरुण चतुर्वेदी के सामने पेंशन समय पर नहीं मिलने की भी शिकायतें आई। सुनवाई के दौरान जयपुर के एक छात्रावास में रखी ट्राईसाइकिलों के बारे में जब डॉ. चतुर्वेदी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में आया है। भामाशाह कैम्प पूरे होने के बाद अलग से कैम्प लगाकर साइकिलें वितरित करवाई जाएगी। उन्होंने ट्राईसाइकिलों के वितरण में हुई गड़बड़ी के लिए पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों को जिम्मेदार भी ठहराया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वोट लेने के चक्कर में कांग्रेस सरकार ने ज्यादा ट्राईसाइकिल खरीद ली थी।

भाजपा प्रदेश कार्यालय पर गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पंचायत राज मंत्री सुरेन्द्र गोयल, सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक और गोपालन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनी।
फोटो : राष्ट्रदूत

तबादला पावर : जनसुनवाई के दौरान शिक्षक तबादलों पर पंचायतीराज मंत्री का खुलासा, कहा...

'तबादले देवनानी करेंगे, अंतिम मुहर मेरी'

डेली न्यूज़ ब्यूरो जयपुर ▷ 11 जून

भाजपा सरकार में शिक्षक तबादलों को लेकर मंत्री अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं ताकि उनकी पकड़ बरकरार रहे। पंचायतीराज शिक्षकों के

तबादलों के मामले में गुरुवार को पंचायतीराज मंत्री सुरेंद्र गोयल ने इसी पावर को दिखाया। गोयल ने कहा है कि पंचायतराज शिक्षकों के तबादले भले ही शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी करेंगे मगर उस पर अंतिम मुहर मेरी ही लगेगी, क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंत्रियों के जनसुनवाई कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री होने के नाते तबादलों में अंतिम अनुमोदन मेरा ही रहेगा। गौरतलब है कि सरकार में पंचायतराज सहित शिक्षा विभाग के तबादले शिक्षा राज्यमंत्री होने के नाते देवनानी करेंगे। मुख्यालय में सुनवाई के दौरान तबादला कराने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा रही। अधिकांश कार्यकर्ता अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों के तबादलों की डिजायर लेकर आए हुए थे। पिछले कई दिनों से सुनवाई कार्यक्रम में कार्यकर्ता तबादलों को लेकर ही आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच ने बताया कि जन सुनवाई कार्यक्रम में आई शिकायतों को लेकर मंत्रियों के जवाब आने लगे हैं। इसमें उन्हें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है।

भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को सुनवाई करते मंत्री अजय सिंह किलक, ओटाराम देवासी व अरुण चतुर्वेदी।

इन्होंने भी सुनी समस्याएं

मुख्यालय में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने पेंशन नहीं आने व अन्य मामलों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को हाथों हाथ निर्देश देकर उन्हें पूरा करने को कहा। इसके अलावा सहकारिता राज्य मंत्री अजय सिंह किलक और गोपालन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी से भी भाजपा कार्यकर्ता मिले और समस्याएं बताकर उन्हें दूर करने को कहा। दोनों मंत्रियों ने समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।

मुख्यालय में कार्यशाला आज

भाजपा के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दो सौ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को इस अभियान को शुरू करने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए जाएंगे।

भाजपा सांसद-विधायक की भी नहीं हो रही सुनवाई : गहलोत

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को भाजपा सरकार पर बरसे। गहलोत ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में इतने कम समय में राज्य सरकार के प्रति आमजन का विश्वास गिरते हुए पहली दफा देखा है। राज्य सरकार के विधायक व सांसद भी सुनवाई नहीं होने का दुखड़ा सुना रहे हैं।

गहलोत ने गुरुवार को यहां थर्मल विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की रिफाइनरी के प्रति सोच सही नहीं है। इस वजह से रिफाइनरी परियोजना अधरझूल में है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चालीस हजार करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी स्थापित करने की परियोजना तैयार की गई थी। राज्य में सत्ता बदलते ही भाजपा सरकार ने योजना के प्रति भ्रांतियां फैलाई जबकि परियोजना में राज्य सरकार की भागीदारी थी। इस परियोजना को स्वीकृत करवाने के लिए तत्कालीन केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री स्तर तक कई बार बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार कांग्रेस राज में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने अथवा नाम बदलने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार को पुरानी योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ नई योजनाएं भी चालू करनी चाहिए, ताकि आमजन को फायदा हो सके।

शिक्षण संस्थानों की लापरवाही से 2 लाख स्कॉलरशिप रिजेक्ट

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने अभियान चलाकर निपटाए तीन साल पुराने मामले, 7 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत

लोकेश प्रसाद आनन्द | जयपुर

शिक्षण संस्थानों व विद्यार्थियों की लापरवाही के कारण सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से बीते 3 वर्षों के दौरान मिलने वाली स्कॉलरशिप में से 2 लाख 2 हजार 491 विद्यार्थियों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 7 लाख 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं लंबित मामलों की संख्या 64 हजार है। विभाग का कहना है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों का यह रिजेक्शन अस्थायी है।

बीते 3 सालों की छात्रवृत्ति के पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए विभाग ने अभियान चलाया है। स्कॉलरशिप आवेदनों की कमियों को विभाग ने बताकर शिक्षण संस्थानों को वापस किया।

> अगर विद्यार्थी जागरूक होते, तो 2 लाख से अधिक आवेदन रिजेक्ट नहीं हो पाते। 7 लाख 50 हजार छात्रवृत्ति आवेदन के साथ-साथ उनमें से अधिकांश आवेदन को स्वीकृति मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर शिक्षण संस्थान दोषी पाए जाएंगे, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
>
> - हरसहाय मीणा, अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

आवेदन फार्म में इस तरह की कमियां

जाति प्रमाण पत्र न देना, हस्ताक्षर न होना, जन्म तिथि न होना, अंक न भरना या गलत भरना, फोटो सहित अन्य कमियां या गलतियां थीं। लेकिन शिक्षण संस्थानों ने इनमें से अधिकांश को कमियों सहित भेज दिया। उधर शिक्षण संस्थानों के मुताबिक विद्यार्थियों ने लापरवाही दिखाई। उन्होंने विभाग द्वारा बताई गई कमियों को दूर ही नहीं किया। कमियों को दूर किए बिना नियमित छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती।

स्कॉलरशिप पेंडिंग रखी तो संस्थान ब्लैक लिस्टेड होंगे

17 अप्रैल को विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक छात्रवृत्ति आवेदन को पेंडिंग रखने वाले शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति के लिए ब्लैक लिस्टेड किए जा सकते हैं। संस्था प्रधान या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही एससी, एसटी, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई। 30 जून तक संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों के पास आवेदन लंबित रहने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के पहले ये थे हालात

छात्रवृत्ति के कुल आवेदन वित्त वर्ष 2014-15 में 360479, 2013-14 में 397498 और 2012-13 में 275544 आवेदन आए। अभियान के पहले वित्त वर्ष 2014-15 में 226315, 2013-14 में 40239 और 2012-13 में 23088 छात्रवृत्ति के आवेदन सेंक्शन होने के लिए पेंडिंग थे। इसमें वित्त वर्ष 2014-15 में 90135, 2013-14 में 74175 और 2012-13 में 38131 छात्रवृत्ति के आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं।

कलेक्टर्स को मिली नई टवेरा

जयपुर | स्टेट मोटर गैराज मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राज्य के सभी 33 जिला कलेक्टरों को स्टेट मोटर गैराज की ओर से नवीन शेवरले टवेरा वाहनों का आवंटन किया गया है। डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि जिला पूल अतिविशिष्ट व्यक्तियों, एयर-क्रू, विधानसभा सदस्यों एवं लोकसभा सदस्यों के उपयोग के लिए भी शेवरले टवेरा उपलब्ध कराई गई है।